# वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2019-20

**अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन**

कच्चे तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि और अनेक वैश्विक बाधाओं के बावजूद 2017-18 में दर्ज की गई 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत (केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार) वृद्धि हासिल करने का अनुमान है। वृहत आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधारों, मुख्य रूप से चालू संरचनात्मक सुधारों में मजबूती, राजकोषीय अनुशासन, सेवाओं की सक्षम प्रदायगी और वित्तीय समावेशन के चलते अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि हासिल की गई है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2012-13 में 9.9 प्रतिशत से काफी हद तक गिर कर 2017-18 में 3.6 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वहनीय सीमा (3.7 प्रतिशत) के भीतर थी और आगामी महीनों में इसमें और नरमी आ सकती है। उच्चतर प्रट्रोलियम, तेल और स्नेहक आयातों के कारण मुख्यतः अधिक व्यापार घाटे के चलते चालू खाता घाटा 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी का 2.7 प्रतिशत हो गया है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर आ रहा है जैसाकि विश्व बैंक की व्यापार करना आसान बनाना 2019 रिपोर्ट में दर्शाया गया है, इससे भारत रैंकिंग में 23 स्थान के सुधार के साथ 2018 में 77वें स्थान पर आ गया है।

सतत बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित 2018-19 में 7.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है जबकि 2017-18 में 6.5 प्रतिशत हासिल किया गया था। 2018-19 में, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 3.8 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। नियत निवेश और माल तथा सेवाओं के निर्यातों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नियत निवेश में वृद्धि 2017-18 में 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 12.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। इससे नियत निवेश दर में वृद्धि होने की संभावना है जो पिछले 3 वर्षों में एक सी बनी रही। वर्ष 2018-19 में माल और सेवाओं के निर्यात में 12.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2017-18 में इसमें 5.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। जीडीपी में कुल उपभोग व्यय का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वसनीयता बढ़ी है । वर्ष में किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैंः अवसंरचना विकास को बढ़ावा; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऐतिहासिक सहायता और आउटरीच कार्यक्रम; 2018-19 के मौसम के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों हेतु बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य; वार्षिक ₹250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कम आयकर और व्यापार करना आसान बनाने में सुधार लाने हेतु और भी उपाय शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था के मार्ग में आने वाली महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक चुनौतियों में अनेक वैश्विक बाधाएं जैसेकि व्यापार में बढ़ते दबाव और विश्व के कुछ भागों में भौगोलिक-राजनैतिक अनिश्चितताएं और बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति शामिल हैं। बहरहाल, किए गए संरचनात्मक सुधारों, निवेश दर में सुधार, कच्चे तेल की कीमत में गिरावट तथा विनिमय दर में स्थिरता के आलोक में मध्यावधिक वृहत सम्भावना उज्ज्वल है।

**मूल्य**

अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिश्र (सीपीआई-सी) पर आधारित मुद्रास्फीति का औसत 3.7 प्रतिशत रहा। जुलाई, 2018 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिश्र (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति लगातार नरम रही है। यह नवम्बर, 2018 में 2.3 प्रतिशत से गिरकर दिसम्बर, 2018 में 2.2 प्रतिशत पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समिश्र (सीपीआई-सी) 2017- 2018 में 3.6 प्रतिशत और 2016.17 में 4.5 प्रतिशत थी। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान खाद्य मुद्रा स्फीति (उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक) का औसत 0.5 प्रतिशत है। यह दिसम्बर, 2018 में (-) 2.5 प्रतिशत था। खाद्य मुद्रास्फीति 2017-18 में 1.8 प्रतिशत और 2016-17 में 4.2 प्रतिशत थी।

अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति का औसत 4.8 प्रतिशत था। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2017-18 में 3.0 प्रतिशत और 2016-17 में 1.7 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में ईंधन का भारांश अधिक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांश अधिक रहा है। कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के साथ 2016-17 से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगी। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान, थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति का औसत (-) 0.2 प्रतिशत रहा। थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति 2017-18 में 1.9 प्रतिशत और 2016-17 में 5.8 प्रतिशत थी।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए वहनीय स्तर (+/ -) 2 प्रतिशत के साथ मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत निर्धारित किया है।

**केन्द्र सरकार के वित्त साधन**

वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था 2017-18 में 3.2 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का लगभग 3.3 प्रतिशत पर ₹6,24,266 करोड़ की गई थी। चूंकि राजकोषीय घाटे में 2017-18 मामूली वृद्धि हुई, 2018-19 में इसका स्तर मामूली रूप से ऊपर रखा गया था। मामूली वृद्धि होने के बावजूद राजकोषीय घाटे और जीडीपी का अनुपात जीडीपी के 3 प्रतिशत के अपने लक्षित स्तर को हासिल करने के लिए सही रास्ते पर है। 2018-19 में राजस्व घाटे की बजट व्यवस्था ₹4,16,034 करोड़ पर जीडीपी का 2.2 प्रतिशत थी।

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) में सकल कर और जीडीपी का अनुपात 12.1 प्रतिशत और कुल व्यय और जीडीपी का अनुपात 13.0 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई थी। सकल कर राजस्व की परिकल्पित वृद्धि 2017-18 (सं.अ.) की तुलना में 16.7 प्रतिशत थी। 2018-19 में कुल व्यय की बजट व्यवस्था 2017-18 (सं.अ.) की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ाकर की गई थी।

अप्रैल-नवम्बर, 2018 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्रीय सरकार के वित्त साधन संबंधी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में सकल कर राजस्व (अर्थात राज्यों को कर अंतरण के पहले) 7.1 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-नवम्बर, 2018 के दौरान भी सकल कर राजस्व 2018-19 के लिए बजट व्यवस्था के स्तर का 51.3 प्रतिशत हासिल किया गया। इसी अवधि के दौरान कर भिन्न राजस्व में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 57.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 2018-19 के बजट व्यवस्था के स्तर का 28.5 प्रतिशत पर रहा।

अप्रैल-नवम्बर, 2018 के दौरान प्रमुख सब्सिडियों में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017 की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2018 के दौरान खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी में क्रमशः ₹7,161 करोड़, ₹4,092 करोड़ और ₹1,725 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

अप्रैल-नवम्बर, 2018 में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा ब.अ. के क्रमशः 114.8 प्रतिशत और 132.6 प्रतिशत था, जो उसी अवधि के लिए उनके 5 वर्ष के औसत से अधिक था। सं.अ. में 2018-19 में राजकोषीय और राजस्व घाटा को क्रमशः जीडीपी का 3.4 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत रखा गया।

**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता**

वर्ष 2018-19 में, अब तक मौद्रिक नीति समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई थीं। 2018-19 के लिए दूसरी (जून, 2018) और तीसरी (अगस्त, 2018) द्विमासिक बैठकों में मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो दर में प्रत्येक में 25 आधार बिन्दुओं तक वृद्धि करने का निर्णय लिया। इन दरों को अक्तूबर और दिसम्बर दोनों द्विमासिक बैठकों में अपरिवर्तित रखा गया था। परिणामस्वरूप जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार रेपो दर 6.50 प्रतिशत थी। नकदी समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर 6.25 प्रतिशत थी, सीमांत स्थली सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत थी।

वर्ष 2018-19 की पहली दो तिमाहियों में, नकदी की स्थिति सुखद थी और अधिकांशतः अतिरिक्त थी। अप्रैल, 2018 और सितम्बर, मध्य 2018 के बीच औसतन लगभग ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध थी। बहरहाल, 15 और 26 सितम्बर, 2018 के बीच इसमें तुरंत ही लगभग ₹1,18,000 करोड़ की कमी हो गई। नकदी के दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹30000 करोड़ के खुले बाजार प्रचालनों की घोषणा की। अस्थायी रूप से नकदी की स्थिति सुधरी परंतु 15 अक्तूबर के बाद इसमें कमी आने लगी। तबसे नकदी घाटा का औसत लगभग ₹90000 करोड़ रहा। 26 दिसम्बर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार नकदी घाटा बहुत अधिक ₹1.8 लाख करोड़ था।

**बैंकिंग क्षेत्र**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च, 2018 में 11.5 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2018 में 10.8 प्रतिशत पर आ गया, जो आस्ति गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है। इस अवधि के दौरान उनकी निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में भी गिरावट दर्ज की गई। निःशक्त आस्ति भार से उबरने की संभावना के आलोक में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों के सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में मार्च, 2015, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा शुरू होने के पहले समाप्त वित्तीय वर्ष, से पहली बार अर्धवार्षिक गिरावट देखी गई।

वर्षानुवर्ष आधार पर, खाद्य-भिन्न बैंक ऋण में नवम्बर, 2018 में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। जबकि नवम्बर, 2017 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवम्बर, 2018 में सेवा क्षेत्र को ऋण में 28.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि नवम्बर, 2017 में इसमें 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवम्बर, 2018 में वैयक्तिक ऋण में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि नवम्बर, 2017 में इसमें 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

**विदेशी क्षेत्र**

पण्य वस्तु का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 222.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 245.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह 2017-18 में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुकूल रहा। वर्ष 2017-18 में भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात (सीमा शुल्क आधार पर) का मूल्य 303.5 बिलियन अमरीकी डालर था।

अप्रैल-दिसम्बर, 2017 में पण्य वस्तुओं का आयात 343.3 बिलियन अमरीकी डालर से 12.6 प्रतिशत बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 386.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह वृद्धि, 2017-18 के दौरान हासिल की गई 21.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में पेट्रोलिय, तेल और स्नेहकों (पीओएल)का आयात 75.7 बिलियन अमरीकी डालर से अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में 42.9 प्रतिशत बढ़कर 108.1 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया। अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के लिए गैर पीओएल आयात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 267.7 बिलियन अमरीकी डालर से 4.1 प्रतिशत बढ़कर 278.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 120.6 बिलियन अमरीकी डालर से अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान बढ़कर 141.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

अर्ध वार्षिक स्तर पर अगर हम इसकी तुलना करें तो यह देखा जा सकता है कि भारत का चालू खाता घाटा 2018-19 की पहली छमाही में बढ़कर 35.1 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.7 प्रतिशत) हो गया जबकि 2017-18 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर) में यह 21.9 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) था। इस अवधि के दौरान व्यापार घाटा 2017-18 की पहली छमाही में 74.4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 95.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। निवल अदृश्य अधिशेष, निवल सेवाओं और निवल निजी अंतरणों दोनों में देखी गई वृद्धि के चलते 2017-18 की पहली छमाही में 52.5

बिलियन अमरीकी डालर से 2018-19 की पहली छमाही में बढ़कर 60.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

2018-19 की पहली छमाही के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 17.7 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2017-18 की पहली छमाही में यह 19.6 बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि निवल पोर्ट फोलियो में परिवर्तन पिछले वर्ष की पहली छमाही में 14.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2017-18 की पहली छमाही में (-) 9.8 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में पिछले वर्ष की पहली छमाही के दौरान 30.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2018-19 की पहली छमाही के दौरान 24.0 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि स्टाक में गिरावट आई जो 2018 में सितम्बर अंत में 400.5 बिलियन अमरीकी डालर रह गया था। 28 दिसम्बर, 2018 को विदेशी मुद्रा आरक्षित स्टाक 393.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

अप्रैल-दिसम्बर, 2019 में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) प्रति अमरीकी डालर ₹69.74 थी। रुपये का मूल्यह्रास होकर मार्च, 2018 में प्रति अमरीकी डालर ₹65.02 से दिसम्बर, 2018 में प्रति अमरीकी डालर ₹70.72 पर आ गया।

**कृषि**

प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2018-19 में खरीब खाद्यानों का कुल उत्पादन 141.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2018-19 के खरीफ मौसम के अनुसार चावल का उत्पादन 99.2 मिलियन टन अनुमानित है। 2018-19 (केवल खरीफ) में तिलहनों का उत्पादन 22.2 मिलियन टन अनुमानित है।

2016-17 में 275.2 मिलियन टन की तुलना में 2017-18 (चौथा अग्रिम अनुमान) में खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन 284.8 मिलियन टन हुआ था। 2017-18 में चावल और गेहूँ में भी रिकार्ड उत्पादन क्रमशः 112.9 मिलियन टन और 99.7 मिलियन टन हुआ था। 2017-18 में दालों का उत्पादन भी बढ़कर 25.2 मिलियन टन हुआ, जो 2016-17 में हासिल किए गए पहले के रिकार्ड उत्पादन से 2.1 एक मिलियन टन अधिक था। 2017-18 के दौरान देश में तिलहनों का उत्पादन 31.3 मिलियन टन अनुमानित है। सितम्बर, 2018 तक कृषि ऋण का संवितरण 6.5 लाख करोड़ रुपये हुआ था जबकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इसका लक्ष्य ₹11 लाख करोड़ था।

**औद्योगिक उत्पादन**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में अप्रैल-नवम्बर, 2018 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान यह 3.2 प्रतिशत थी। अप्रैल-नवम्बर, 2018 में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में क्रमशः 3.7 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की उपयोग आधारित श्रेणियों के संबंध में, अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं और अवसंरचना/ निर्माण संबंधी वस्तुओं के क्षेत्रों में क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल की गई है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत बढ़ा।

आठ प्रमुख अवसंरचना उद्योगों में, अप्रैल-नवम्बर, 2017 के दौरान 3.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2018 के दौरान 5.1 प्रतिशत की संचित वृद्धि दर्ज की गई। उनमें वर्ष 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

**संभावनाएं**

वर्ष 2018-19 में किए गए सुधार के उपायों से वृद्धि की गति सुदृढ़ और संबलित होने की आशा है। वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का उभरते वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के आलोक में आकलन किए जाने की आवश्यकता है। उभरते व्यापारिक दबावों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को कतिपय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में निवेश क्रियाकलाप का पुनरूद्धार हुआ है और नियत निवेश की वृद्धि में हालिया तेजी के आगामी वर्ष में बरकरार रहने की आशा की जा सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की मामूली वृद्धि 11.5 प्रतिशत हो सकती है।

# वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
## (आर्थिक निष्पादन : एक दृष्टि में)

| क्र.सं. | मद | निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर | | प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| **संपदा क्षेत्र** | | | | | |
| 1. | बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)@ | | | | |
| | (क) वर्तमान मूल्यों पर | 16773 | 18841 | 10.0 | 12.3 |
| | (ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर | 13011 | 13952 | 6.7 | 7.2 |
| 2. | औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100)* | 121.6 | 127.7 | 3.2 | 5.0 |
| 3. | थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100) | 114.5 | 119.9 | 2.9 | 4.8 |
| 4. | उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः नई श्रृंखला (2012=100) | 134.5 | 139.5 | 3.3 | 3.7 |
| 5. | मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़) | 13208.7 | 14551.6 | 3.3 | 4.2 |
| 6. | वर्तमान मूल्यों पर आयात** | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 2214371 | 2697307 | 18.7 | 21.8 |
| | (ख) मिलियन अमरीकी डालर | 343340 | 386650 | 23.5 | 12.6 |
| 7. | वर्तमान मूल्यों पर निर्यात** | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 1436614 | 1711906 | 7.3 | 19.2 |
| | (ख) मिलियन अमरीकी डालर | 222767 | 245440 | 11.7 | 10.2 |
| 8. | व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)** | -120572 | -141210 | 53.7 | 17.1 |
| 9. | विदेशी मुद्रा भंडार (28 दिसंबर 2018 तक) | | | | |
| | (क) ₹ करोड़ | 2614760 | 2752310 | 7.3 | 5.3 |
| | (ख) मिलियन अमरीकी डालर | 409072 | 393404 | 14.0 | -3.8 |
| 10. | चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)## | -21935 | -35054 | | |
| | **सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)#** | | | | |
| 1. | राजस्व प्राप्तियां | 804861 | 870306 | 1.1 | 8.1 |
| | सकल कर राजस्व | 1087302 | 1164685 | 16.5 | 7.1 |
| | कर (केन्द्र को निवल) | 699392 | 731669 | 12.6 | 4.6 |
| | कर-भिन्न राजस्व | 105469 | 138637 | -39.7 | 31.4 |
| 2. | पूंजी प्राप्तियां (जिसमें) | 673954 | 742902 | 37.4 | 10.2 |
| | ऋणों की वसूली | 9471 | 10467 | 4.8 | 10.5 |
| | अन्य प्राप्तियां | 52378 | 15810 | 122.6 | -69.8 |
| | उधार और अन्य देनदारियां | 612105 | 716625 | 33.6 | 17.1 |
| 3. | कुल प्राप्तियां (1+2) | 1478815 | 1613208 | 14.9 | 9.1 |
| 4. | कुल व्यय (क)+(ख) | 1478815 | 1613208 | 14.9 | 9.1 |
| | (क) राजस्व व्यय | 1294700 | 1421778 | 13.1 | 9.8 |
| | ब्याज भुगतान | 309799 | 348233 | 16.2 | 12.4 |
| | प्रमुख सब्सिडियां | 206068 | 219046 | 4.2 | 6.3 |
| | पेंशन | 111593 | 130079 | 37.6 | 16.6 |
| | पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 128434 | 134787 | 13.7 | 4.9 |
| | (ख) पूंजी व्यय | 184115 | 191430 | 29.3 | 4.0 |
| 5. | राजस्व घाटा | 489839 | 551472 | 40.7 | 12.6 |
| 6. | प्रभावी राजस्व घाटा | 361405 | 416685 | 53.6 | 15.3 |
| 7. | राजकोषीय घाटा | 612105 | 716625 | 33.6 | 17.1 |
| 8. | प्राथमिक घाटा | 302306 | 368392 | 58.0 | 21.9 |

*@ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2018-19 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।*

** अप्रैल-नवंबर*

*** सीमाशुल्क आधार पर*

*# अप्रैल-नवंबर और महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।*

*## अप्रैल - सितंबर*